

भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

प्रलम्ब के लिये:

[वक्सति राष्ट्र का दर्जा](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक](#), [पूँजी नरिमाण](#), [सतत् विकास](#), [लो-कारबन इकॉनमी](#), [नवीकरणीय ऊर्जा](#), [वित्तीय समावेशन](#), [बैंकों का नज़ीकरण](#), [हरति परयोजनाएँ](#), [इक्वटी बाज़ार](#), [बेसल समति](#), [कॉरपोरेट बाँण्ड](#)

मेन्स के लिये:

[बैंकों का नज़ीकरण](#), [बेसल समति](#), [वक्सति राष्ट्र का दर्जा](#)

[स्रोत: लाइव मटि](#)

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ के समय तक एक वक्सति राष्ट्र बनने का भारत का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य इस बात पर नरिभर करता है कि उसका वित्तीय क्षेत्र कतिनी अच्ची तरह से वक्सति है।

भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र किस प्रकार सहयोग कर सकता है?

- **सतत् उच्च वृद्धि:** [भारतीय रज़िर्व बैंक](#) द्वारा कयि गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत को वक्सति राष्ट्र बनने के लिये आगामी 25 वर्षों तक **7.6% वार्षिक दर से विकास** करने की आवश्यकता है।
 - उच्च विकास दर को दीर्घावधि तक बनाए रखने के लिये एक **स्थिर, कुशल और अभनिव वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता** होगी जो **मैक्रो-वित्तीय स्थिरता से समझौता कयि बना** भारतीय परिवारों तथा व्यवसायों एवं सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करे।
- **बचत का एकत्रीकरण:** [पूँजी नरिमाण](#) हेतु **घरेलू एवं बाहरी दोनों स्रोतों पर ध्यान केंद्रति करते हुए पूँजी संचय तीव्रता से होना** चाहयि।
 - वतित एवं पूँजी की मांग **बड़े पैमाने पर बुनयिदी ढाँचा परयोजनाओं**, वनिरिमाण की बढ़ती आवश्यकताओं, **औपचारिक अर्थव्यवस्था के वसितार** और बढ़ती व्यापार गतविधियों से उत्पन्न होगी।
 - वतित एवं पूँजी की आपूर्ति के लिये **घरेलू बचत, चरिस्थायी वदिशी पूँजी जुटाने और जमा, ऋण तथा इक्वटी बाज़ारों को सुदृढ़ करने** की आवश्यकता है।
- **बैंकगि क्षेत्र की भूमिका:**
 - नए वित्तीय संस्थान की आवश्यकता: **डजिटल, थोक/नविश और वशिषिट बैंकों** सहति वभिनिन आकारों के बैंकों तथा **NBFC** की एक वविधि श्रेणी वित्तीय समावेशन का समर्थन करने एवं बड़े पैमाने की परयोजनाओं को नधि प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
 - **फनितेक कंपनयिों** की भूमिका: **वित्तीय पहुँच और समावेशन को आगे बढ़ाने तथा आने वाले वर्षों में बैंकगि एवं वित्तीय प्रणाली में दकषता बढ़ाने में फनितेक कंपनयिों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।**
 - रज़िर्व बैंक की नीतयिों के अनुसार फनितेक कंपनयिों अपनी बैलेंस शीट पर ऋण नहीं दे सकती हैं, जसिके परणामस्वरूप प्रत्यक्ष वित्तीय जोखमि भी कम हो गए हैं।
 - **बैंकों का नज़ीकरण:** मार्च 2024 की तमिाही की बैंक बैलेंस शीट के अनुसार, सात PSB के पास शुद्ध **NPA** में ऋण अग्रमि का 1% से भी कम है। कोई भी PSB अब भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के **तवरति सुधारतमक कार्रवाई फरेमवरक** के तहत नहीं है जो ऋण प्रतबिंध लगाता है।
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नज़ीकरण करने से नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और वेतन संबंधी प्रतबिंध हट जाएंगे, जसिसे बैंकगि क्षेत्र में समानता आएगी, उनकी लाभप्रदता तथा मूल्यांकन में वृद्धि होगी एवं संभवतः वे नज़ी बैंकों के बराबर आ जाएंगे, जसिसे ऋण तक पहुँच, नविश व रोज़गार वृद्धि को लाभ होगा।
- **पूँजी बाज़ार की भूमिका:**
 - सरकार का लक्ष्य है कि भारत **वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन** तक पहुँच जाए और वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन को कम कर दे, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक परयोजनाओं तथा योजनाओं के लिये वतित पर नरिभर करेगा।
 - **ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** को पार करने वाले बाज़ार पूँजीकरण के साथ भारतीय बाज़ार अब आकार के मामले में **मेशिव में चौथे स्थान पर है**, जो अमेरिका, चीन और जापान की तुलना में पीछे है। हाल ही में बाज़ार पूँजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात

150% को पार कर गया है।

- भारतीय पूंजी बाज़ार तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूलन ढालने में सुसज्जति है, यह नियामकों के साथ-साथ संस्थान और प्रतभागी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग करने में कुशल है, जो भारत के विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिये इक्विटी बाज़ारों की स्थितिका नरिमाण करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र को कनि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- वित्तीय पहुँच का वसितार करने और दक्षता में सुधार करने में फनिटेक कंपनियों की भूमिका के बावजूद उनकी तीव्र वृद्धिग्राहकों की सुरक्षा तथा बैंकों एवं गैर-बैंकों दोनों के लिये संभावित अपरत्यक्ष जोखिम जैसी चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है।
- उभरते केंद्रीकृत जोखिमों के बारे में भी चिंताएँ हैं क्योंकि बड़ी तकनीकी कंपनियाँ फनिटेक क्षेत्र पर तेज़ी से हावी हो रही हैं। फनिटेक कंपनियाँ, जो वर्तमान में अनयिमति हैं, व्यवहार्यता और प्रभावशीलता की चुनौतियों के बावजूद परत्यक्ष वनियामक नरिक्षण की माँग का सामना करती हैं।
- डिजिटल लेंडिंग, बाय नाउ पे लेटर (BNPL) और पे-एज़-यू-गो स्कीम्स के तीव्र पैमानों (Rapid Scale) को अपनाने की दरों के कारण संभावित अति-वसितारण तथा वविक रहति उत्साह (Irrational Enthusiasm) संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
 - सामान्य जोखिमों में गलत बकिरी और अत्यधिक जोखिम शामिल हैं।
- डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और परचालन संबंधी मुद्दों से जुड़े जोखिमों से एक चुनौती उत्पन्न होती है, जसि पर भी वचिर कथिा जाना चाहयि।
- PSB अपनी बैलेंस शीट में सुधार के बावजूद भारतीय नजी बैंकों की तुलना में प्राइस-टू-बुक गुणक के साथ काफी कम संघर्ष करते हैं, जो संभावित रूप से कम प्रदर्शन का संकेत देता है।
- नजी बैंक प्रायः जमा पूंजी के लिये प्रतसिप्रद्धा करने की आवश्यकता से बचने के लिये न्यून ऋण वृद्धि लेकनि उच्च मारजनि बनाए रखने का वकिलप चुनते हैं।
 - इसके परिणामस्वरूप जमा दरें कम हो जाती हैं, जसिसे भारतीय बचतकर्त्ता इक्विटी और आवास नविश को प्राथमकता दे सकते हैं, जसिसे जमा वृद्धि के लिये चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- भारत के अवकिसति कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार को अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये सरकार के तत्काल ध्यान की आवश्यकता है।

आगे की राह

- बैंकिंग क्षेत्र:
 - बैंकों की पर्याप्त पूंजी आवश्यकताओं के कारण व्यापारिक और औद्योगिक घरानों, नजी इक्विटी, उद्यम पूंजी कोषों तथा वदिशी बैंकों को बैंकों में महत्त्वपूर्ण हसिसेदारी की अनुमतदिने की अनचिछा पर पुनर्वचिर कथिा जाना चाहयि।
 - यह सुनश्चिति करने के लिये कबैंक, NBFC और फनिटेक कंपनियाँ अत्यधिक उत्साह की प्रवृत्ति के बावजूद सुरक्षति, संरक्षति तथा कुशलतापूरवक काम करें, बैंकिंग प्रणाली हेतु मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था स्थापति करने एवं उस पर वचिर-वमिर्श करने की आवश्यकता है।
 - अंतरराष्ट्रीय नपिटान बैंक (BIS) के अंतरगत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समतिद्वारा वकिसति सुस्थापति सुरक्षा उपायों को अपनाना और लागू करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जनिहें वैश्विक वित्तीय विकास तथा अनुभवों के आधार पर कई वर्षों के दौरान परषिकृत कथिा गया है।
- पूंजी और प्रतभूत बाज़ार:
 - तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों द्वारा बाज़ार जोखिमों के कमज़ोर आकलन से रोकने के लिये वनियामक ध्यान बढ़ाने की आवश्यकता है। वनियामकों को संभावित मुद्दों का अनुमान लगाना चाहयि और नवाचार हेतु जगह छोड़ते हुए सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहयि।
 - सर्वोच्च प्राथमकता सरकारी प्रतभूतियों और कॉरपोरेट बॉण्डों के लिये बॉण्ड बाज़ार वनियमन को एकीकृत करना तथा नविशकों, व्यापारियों एवं हतिधारकों हेतु प्रकरथिाओं को सरल बनाना होना चाहयि।
 - विकासशील बॉण्ड बाज़ार पर ध्यान केंद्रति कथिा जाना चाहयि, क्योंकि यह हरति और ऊर्जा परविरतन परथिोजनाओं के वतितपोषण के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो तेज़ी से वदिशी नविश पर नरिभर होंगे, जसिके लिये वशिषिट सुवधिजनक उपायों की आवश्यकता होगी।
- अन्य उपाय:
 - बैंकों के अलावा वित्तीय क्षेत्र के अन्य भागों, जैसे बीमा और ऊर्जा क्षेत्र के वतित का नजीकरण भी एक साथ उटाए जाने वाले कदमों के रूप में वचिर कथिा जाना चाहयि।
 - भारत में शहरी बुनयिादी ढाँचे का पुनरुद्धार अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, वशिष रूप से यह देखते हुए कानुमान है कविर्ष 2050 तक 800 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में नवास करेंगे, हालाँकि वरिष 2015 से नगरपालिका बॉण्ड को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद नगरपालिकाएँ विकास परथिोजनाओं के लिये संसाधनों तथा वतितपोषण की कमी से जूझ रही हैं।
 - परथिोजना वतितपोषण पर भारतीय रज़िर्व बैंक के हाल के वविकपूरण दशिा-नरिदेशों के अनुरूप प्रतचिक्रीय बफरस और मानक परसिंपत्तियों के लिये प्रावधानों के कारयान्वयन पर वचिर कथिा जाना चाहयि।

दृष्टि मैनस प्रश्न:

प्रश्न. वर्ष 2047 तक वकिसति राषट्र का दर्जा प्राप्त करने की दशिा में देश की यात्रा को सुवधिजनक बनाने में भारत के वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 1. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापति स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं वनियिमन कयिा जाता है ।
2. वे इक्वटिी शेयर और अधमिन शेयर जारी कर सकते हैं ।
3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन द्वारा बैंकगि वनियिमन अधनियिम, 1949 के कार्य-क्षेत्र में लाया गया था ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन भारत में सभी ATM को जोडता है? (2018)

- (a) भारतीय बैंक संघ
- (b) नेशनल सक्ियोरटिज़ डपिऑज़टिरी लमिटिड
- (c) भारतीय राष्ट्रिय भुगतान नगिम
- (d) भारतीय रज़िर्व बैंक

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहतिों को संस्थागत वत्ति में लाने के लयि आवश्यक है । क्या आप सहमत है कइससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वत्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टीकरणे के लयि तरक परस्तुत कीजयि । (2016)